

स्टेडियम में भगदड़: जेएससीए प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करना पड़ा भारी, लापरवाही ने खड़े किए सवाल

एनएचआरसी तक पहुंचा मामला डीसी और एसएसपी से शिकायत

रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार को झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग के फाइनल मैच के दौरान मची भगदड़ ने आयोजन व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर किया है। इस घटना ने आने वाले राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। क्रिकेट लीग का आयोजन जेएससीए प्रबंधन और एसजे अपलिफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। फाइनल मैच में स्टेडियम के अंदर निर्धारित क्षमता के अनुरूप लगभग 30 हजार दर्शक मौजूद थे। वहीं, हजारों लोग अंदर जाने के लिए बाहर खड़े थे। इस बीच भीड़ बढ़ती गई, लेकिन उसे नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रवेश द्वारों पर अव्यवस्था बढ़ने के बाद हालात बिगड़े और भगदड़ मच गई।

भगदड़ की जांच व जवाबदेही तय करने की मांग: जेएससीए स्टेडियम के बाहर भगदड़ पर एनएचआरसी (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) से शिकायत की गई है। शिकायत करने वाले ज्योति शर्मा ने रांची डीसी और एसएसपी को भी शिकायत पत्र भेजा है। इसमें जिला



जेएससीए स्टेडियम के बाहर मंगलवार की रात में भगदड़ से पहले स्टेडियम में प्रवेश करते दर्शक। • फाइल फोटो

शिकायतकर्ता के साथ क्रिकेटप्रेमियों ने भी खड़े किए सवाल

- बाउंसर को लाठी चार्ज का अधिकार किसने दिया।
- यदि स्टेडियम में प्रवेश नहीं देना था तो बार-बार गेट क्यों खोला।
- मैच को लेकर सोशल मीडिया पर हाइप क्यों किए गए।
- प्रवेश के समय कोई मेटल डिटेक्टर से जांच क्यों नहीं हुई।
- स्टेडियम के बाहर सुरक्षा बल क्यों नहीं थे, बैरिकेडिंग पुख्ता क्यों नहीं।
- इससे भी बड़ा हादसा होता तो इसका कौन जिम्मेदार होता।

प्रशासन, पुलिस व स्टेडियम प्रबंधन से विस्तृत जांच की मांग की गई है। शिकायत पत्र जेएससीए सचिव को भी भेजा गया है। शिकायतकर्ता ने

आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पत्र में आयोजकों की भीड़ प्रबंधन योजना, पर्याप्त सुरक्षा बलों की उपलब्धता और तैनाती,

सुरक्षा प्रोटोकॉल व आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र के अनुपालन, आयोजकों, पुलिस-प्रशासन के बीच समन्वय तथा स्टेडियम क्षमता से

स्टेडियम के अंदर भी मानकों का पालन नहीं

स्टेडियम के अंदर भी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। मूल रूप से बड़े आयोजन के दौरान स्टेडियम में प्रवेश के साथ मेटल डिटेक्टर से लोगों की जांच होती है। साथ ही कई वस्तुओं को साथ ले जाने की अनुमति नहीं होती है, पर मंगलवार को मैच के लिए दर्शकों को बिना किसी जांच के जाने दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय मैचों से पहले सुरक्षा व्यवस्था की चिंता

जेएससीए स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत-वेस्टइंडीज के बीच टी-20 शृंखला का दूसरा मैच होना है। वहीं, 19 से 23 फरवरी 2027 तक भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट होगा। लेकिन भगदड़ ने इन आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था सवाल के घेरे में है।

बाउंसर की ओर से लाठी भांजने से दर्शकों में बढ़ा आक्रोश

स्टेडियम के बाहर और अंदर सुरक्षा बलों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। प्रवेश और निकास मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल नहीं था। निजी सुरक्षा कर्मियों और बाउंसरों के भरोसे भीड़ नियंत्रण की कोशिश की गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ स्थानों पर बाउंसरों के लाठी भांजने और लोगों को धक्का देकर हटाने की कोशिश से भीड़ उग्र हो गई। जब-जब गेट खुलता था, बाउंसर लोगों पर लाठी भांजते रहे।

घायलों को अस्पताल से छोड़ दिया गया है। बहुत बड़ी घटना टल गई। हमें इस तरह की अप्रत्याशित भीड़ होने की उम्मीद नहीं थी। आगे किसी भी आयोजन को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम होंगे।



अजयनाथ शाहदेव, अध्यक्ष, जेएससीए

हमारी ओर से चूक हुई है। हमें इस तरह की भीड़ का अंदाजा नहीं था। आगे हम कोई कमी नहीं करेंगे। किसी प्रकार की सुरक्षा संबंधी परेशानी नहीं होगी। हम क्रिकेटप्रेमियों से भी माफी मांगते हैं, जिन्हें परेशानी हुई।



संजय पांडेय, उपाध्यक्ष, जेएससीए

भविष्य में यदि प्रतियोगिता होगी तो हम टिकट रखने पर विचार करेंगे। इस मामले में जेएससीए के साथ मिलकर निर्णय होगा। सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, इसका आकलन नहीं था।

संभव जैन, निदेशक, एजे अपलिफ्ट

लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों और आयोजकों की जवाबदेही तय करने तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।

हिरासत में हुई 262 मौत के मामलों की फिर होगी जांच

482 मामलों में से 437 न्यायिक तो 45 मौतें पुलिस हिरासत में हुईं

राज्य ब्यूरो, जगमग-रांची : झारखंड में हिरासत में हुई मौतों के 262 मामलों की अब न्यायिक जांच कराई जाएगी। यह निर्णय झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद लिया गया है, जिसमें हिरासत में मौत के मामलों की जांच कार्यपालक दंडाधिकारी से कराए जाने को नियम विरुद्ध बताते हुए न्यायिक दंडाधिकारी से जांच कराने का निर्देश दिया गया था।

अदालत के आदेश के बाद राज्य सरकार ने संबंधित मामलों की जांच की प्रक्रिया पुनः तेज कर दी है। मालूम हो कि वर्ष 2018 से 2025 के बीच राज्य में हिरासत में मौत के कुल 482 मामले सामने आए थे। इनमें 437 मौतें न्यायिक हिरासत में तथा 45 मौतें पुलिस हिरासत में हुई थीं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया था कि इन 482 मामलों में से 220 मामलों की जांच न्यायिक दंडाधिकारी से कराई गई थी, जबकि

वर्ष 2018 से 2025 के बीच राज्य में हुई मौत के मामलों की न्यायिक जांच का झारखंड हाई कोर्ट ने दिया है आदेश



262 मामलों में पुलिस ने न्यायिक जांच के बजाय कार्यपालक दंडाधिकारी से जांच करा दी थी। कोर्ट ने इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों और निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत माना। इसके बाद अब सभी 262 मामलों की फाइलें फिर से खोली जाएंगी। संबंधित जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट नामित करेंगे, जो इन मामलों की जांच करेंगे। अदालत ने सभी जांच छह महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है।

पिट्टाई, आत्महत्या और बीमारी रहे प्रमुख कारण

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि हिरासत में मौत के मामलों के पीछे मुख्य रूप से तीन कारण रहे हैं। कुछ मामलों में पुलिस की पिट्टाई से मौत हुई तो कुछ आरोपितों ने थाने की हाजत या हिरासत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि कई बंदियों की जेल में बीमारी के कारण मौत हो गई। पुलिस हिरासत और थाने की हाजत में हुई मौतों को विशेष रूप से गंभीर श्रेणी का मामला माना गया है। पूर्व में रांची जिले के बुद्ध निवासी रूपेश स्वांसी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में मारपीट की पुष्टि हुई थी। इसी प्रकार पलामू में भी पुलिस द्वारा आरोपित से मारपीट के आरोपों की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हुई थी। अब न्यायिक जांच के जरिए इन सभी मामलों के तथ्यों और जिम्मेदारियों का नए सिरे से परीक्षण किया जाएगा।

262 मौत के मामलों की फिर होगी जांच

झारखंड

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड में हिरासत में हुई मौतों के 262 मामलों की अब न्यायिक जांच कराई जाएगी। यह निर्णय झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद लिया गया है, जिसमें हिरासत में मौत के मामलों की जांच कार्यपालक दंडाधिकारी से कराए जाने को नियम विरुद्ध बताते हुए न्यायिक दंडाधिकारी से जांच कराने का निर्देश दिया गया था। अदालत के आदेश के बाद राज्य सरकार ने संबंधित मामलों की जांच की प्रक्रिया पुनः तेज कर दी है।

मालूम हो कि वर्ष 2018 से 2025 के बीच राज्य में हिरासत में मौत के कुल 482 मामले सामने आए थे। इनमें 437 मौतें न्यायिक हिरासत में

तथा 45 मौतें पुलिस हिरासत में हुई थीं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया था कि इन 482 मामलों में से 220 मामलों की जांच न्यायिक दंडाधिकारी से कराई गई थी, जबकि 262 मामलों में पुलिस ने न्यायिक जांच के बजाय कार्यपालक दंडाधिकारी से जांच करा दी थी।

कोर्ट ने इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों और निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत माना। इसके बाद अब सभी 262 मामलों की फाइलें फिर से खोली जाएंगी। संबंधित जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट नामित करेंगे, जो इन मामलों की जांच करेंगे। अदालत ने सभी जांच छह महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि हिरासत में मौत के मामलों के पीछे मुख्य रूप से तीन कारण रहे हैं। कुछ मामलों में पुलिस की पिटाई से मौत हुई तो कुछ आरोपितों ने थाने की हवालात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि कई बंदियों की जेल में बीमारी के कारण मौत हो गई। पुलिस हिरासत और थाने की हवालात में हुई मौतों को विशेष रूप से गंभीर श्रेणी का मामला माना गया है। पूर्व में रांची जिले के बुंदू निवासी रूपेश स्वांसी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में मारपीट की पुष्टि हुई थी। इसी प्रकार पलामू में भी पुलिस द्वारा आरोपित से मारपीट के आरोपों की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हुई थी।



Source: <https://newstodaynet.com/2026/06/24/nhrc-issues-notice-to-tn-govt-over-tiruvallur-ammonia-leak-deaths/>

NHRC issues notice to TN govt over Tiruvallur ammonia leak deaths

The National Human Rights Commission has taken suo motu cognisance of the tragic ammonia gas leak incident in Tiruvallur that claimed multiple lives.

The National Human Rights Commission has taken suo motu cognisance of the tragic ammonia gas leak incident in Tiruvallur that claimed multiple lives. Acting on media reports, the commission has issued notices to the Tamil Nadu Chief Secretary and the Director General of Police, seeking a detailed report within two weeks.

In its notice, the commission directed the state authorities to submit comprehensive information regarding the incident, including the health condition of the affected workers and details of compensation disbursed to the families of the deceased. The NHRC observed that the incident raises serious concerns of possible human rights violations.

According to available reports, the ammonia leak at a seafood processing unit has so far claimed nine lives. The tragedy reportedly occurred when workers, including women, inhaled toxic gas that leaked from the factory premises while they were resting in a nearby room. The sudden exposure led to severe health complications among several workers.

More than 70 workers who were affected by the leak were rushed to various hospitals in Chennai and Tiruvallur for treatment. Many of them required immediate medical attention due to the hazardous nature of ammonia exposure.

Following the incident, the Tamil Nadu government has ordered a detailed probe and constituted a three-member committee to investigate the circumstances that led to the gas leak. The committee is expected to examine safety protocols, working conditions, and possible lapses at the unit.

The NHRC stated that it will review the report submitted by the state government before deciding on further action. The incident has once again highlighted concerns over industrial safety and the protection of workers' rights in hazardous workplaces.

Source: <https://newstodaynet.com/2026/06/24/gas-leak-tragedy-toll-rises-to-ten-tn-health-dept/>

Gas leak tragedy toll rises to ten: TN Health dept

The fatalities in the Sunday's Ammonia gas leak tragedy at a private seafood processing and export unit in Tiruvallur district of Tamil Nadu rose to 10 on Wednesday with one more affected person—a woman hailing from Odisha—succumbing at the government hospital.

All the deceased were women, with eight of them were natives of Odisha and two from Assam.

Health department officials said of the total 83 affected ,following the gas leak that occurred due to a glitch in the pipeline valve taking gas to ice flakes generator machine, ten had died, five were discharged after treatment and 68 — 65 women and three men — were under treatment. Of them, 17 were under treatment at ICU with ventilator support, 21 were put on oxygen support, while the condition of 30 others were said to be stable.

It may be noted that soon after the tragedy occurred on Sunday, Chief Minister Vijay announced a solatium of Rs two lakhs each to the bereaved families and formed a three-member expert committee headed by Director of Industrial Safety and Health, Member Secretary,Tamil Nadu Pollution Control Board and Additional Director of Public Health, to probe the incident. As mandated by the Chief Minister the committee submitted its report to the government at the state secretariat yesterday.

The National Human Rights Commission also took suo motu cognizance of the gas leak tragedy based on news reports and issued notices to the Tamil Nadu Chief Secretary and the Director General of Police calling for a detailed report on the matter within two weeks.

Source: <https://nagalandpost.com/regional-cooperation-must-respect-state-sovereignty-says-nhrc-chief/>

Regional cooperation must respect state sovereignty, says NHRC chief

NEW DELHI, JUN 23 (PTI): NHRC chairperson Justice V Ramasubramanian (retd) on Tuesday said regional cooperation should be guided by the principles of respect for state sovereignty, non-interference in internal affairs, equality and mutual consideration of national interests.

He made the remarks while virtually participating in the first consultative meeting of national human rights institutions (NHRIs), state bodies and other organisations of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) member states responsible for the protection of human rights and freedoms held in Bishkek in Kyrgyz Republic, the National Human Rights Commission (NHRC) said in a statement.

The NHRC chief welcomed the objectives contained in the draft protocol relating to the exchange of information, dissemination of best practices, expert cooperation and development of coordinated approaches to human rights issues. He noted that regular exchanges among institutions would facilitate mutual learning and enhance institutional effectiveness.

Justice Ramasubramanian, while participating virtually in the meeting, underscored that regional cooperation should be guided by the principles of respect for State sovereignty, non-interference in internal affairs, equality and mutual consideration of national interests, the statement said.

He highlighted the NHRC's Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) capacity-building programme for NHRIs and the value of structured learning, dialogue and cross-border engagement in strengthening institutional capacities.

Justice Ramasubramanian also reaffirmed the NHRC's support for deeper cooperation within the SCO framework and expressed confidence that the consultative mechanism would evolve into an important platform for dialogue, cooperation and exchange of experiences among institutions dedicated to the promotion and protection of human rights and freedoms.

He highlighted that the NHRC, established in 1993, has dealt with nearly 2.37 million cases of human rights violations over the past 32 years, providing valuable institutional experience that could be shared with other member states.

He added that institutions across SCO member states possess rich experiences from which all could benefit through sustained engagement.

The NHRC chief expressed hope that the first consultative meeting would lay the foundation for a durable and practical framework for regional human rights cooperation based on mutual respect, exchange of experiences and a shared commitment to human dignity.

The SCO is a Eurasian political, economic and security alliance founded in 2001, currently comprising nine member states, including India, China, Russia, Pakistan and several Central Asian nations.

Source: <https://www.thehawk.in/news/india/mahayutis-overspending-derailing-maharashtras-financial-legacy-shiv-senaubt-in-saamana>

NHRC seeks reports from CBSE, Maharashtra officials over allegation of extremist content at school event
NHRC Intervenes in Allegations of Extremist Content in Maharashtra School Event

New Delhi, June 24 (IANS) The National Human Rights Commission (NHRC) has sought action taken reports from the Central Board of Secondary Education (CBSE), the Jalna district administration and the Maharashtra Police over allegations that minor children were made to perform to an extremist Pakistani song during an annual day function at a school in Maharashtra's Jalna district.

Acting on a complaint, a Bench of the NHRC presided over by Member Priyank Kanoongo took cognisance of the matter under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, and directed the authorities to inquire into the allegations and submit reports within two weeks. As per a communication issued by the NHRC's Law Division on Wednesday, notices have been issued to the Chairman, CBSE, the District Magistrate, Jalna, and the Superintendent of Police, Jalna.

According to the complaint placed before the apex human rights body, the incident allegedly occurred during an annual day event at Kids World English School in Partur, Jalna district. The complainant alleged that "minor children were made to perform to an extremist Pakistani song promoting violence, accompanied by a background display of terrorist Mumtaz Qadri."

The complaint alleged that after he raised the issue in his capacity as a journalist, the school administration and the Jalna Police launched a retaliatory campaign against him.

The complainant further alleged that following his journalistic whistleblowing to alert authorities, both the school administration and the Jalna police have launched a retaliatory campaign, issuing formal takedown notices to X and threatening him with criminal cases to suppress the investigation," the NHRC said.

Seeking intervention by the apex human rights body, the complainant requested a formal cognisance of the alleged extremist content displayed during the school function, an independent inquiry into the alleged administrative intimidation, and protection for investigative journalists from retaliatory law enforcement action.

Taking note of the allegations, the NHRC observed that the "prima facie seem to be violations of the human rights of the victims". It directed the CBSE Chairman, the District Magistrate and the Superintendent of Police, Jalna, "to get the allegations made in the complaint inquired into and to submit an Action Taken Report within two weeks for perusal of the Commission."



Source: https://timesofindia.indiatimes.com/education/news/pakistani-song-at-maharashtra-school-event-nhrc-issues-notice-to-cbse/amp_articleshow/131969596.cms

'Extremist Pakistani song' at Maharashtra school event: NHRC issues notice to CBSE

National Human Rights Commission (NHRC) on Wednesday sought action taken reports from the Central Board of Secondary Education (CBSE), the Jalna district administration and the Maharashtra Police over allegations that minor children were made to perform to an extremist 'Pakistani' song during an annual day function at a school in Maharashtra's Jalna district.

Taking cognisance of a complaint, a bench of the NHRC led by member Priyank Kanoongo acted under section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993. The commission directed the authorities to investigate the allegations and submit reports within two weeks. According to a communication issued by the NHRC's law division on Wednesday, notices have been sent to the CBSE chairman, the district magistrate of Jalna and the superintendent of police, Jalna.

The complaint relates to an annual day programme at Kids World English School in Partur, Jalna district. According to the complainant, "minor children were made to perform to an extremist Pakistani song promoting violence, accompanied by a background display of terrorist Mumtaz Qadri."

The complainant also alleged that after raising the issue in his capacity as a journalist, he faced action from both the school administration and the local police.

"The complainant further alleged that following his journalistic whistleblowing to alert authorities, both the school administration and the Jalna police have launched a retaliatory campaign, issuing formal takedown notices to X and threatening him with criminal cases to suppress the investigation," the NHRC said.

Seeking the commission's intervention, the complainant asked for formal cognisance of the alleged extremist content displayed during the school event, an independent inquiry into the alleged administrative intimidation, and protection for investigative journalists from retaliatory law enforcement action.

After examining the complaint, the NHRC observed that the allegations "prima facie seem to be violations of the human rights of the victims". The commission directed the CBSE chairman, the district magistrate and the superintendent of police, Jalna, "to get the allegations made in the complaint inquired into and to submit an action taken report within two weeks for perusal of the Commission.

Earlier, a case was registered against the principal and two teachers of the school. The case was filed under provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), including sections dealing with acts affecting the sovereignty, unity and integrity of India, promoting enmity between groups, spreading misinformation affecting national integration, and circulating false information likely to cause public alarm.

However, the school administration strongly denied the allegations. Principal Siddiqui said the music used during the programme was from the popular Turkish television serial Ertugrul Ghazi and not a Pakistani song.

Source:

<https://education.economictimes.indiatimes.com/amp/news/school-education/nhrc-seeks-reports-from-cbse-maharashtra-officials-over-allegation-of-extremist-content-at-school-event/131972688>

NHRC seeks reports from CBSE, Maharashtra officials over allegation of extremist content at school event
Acting on a complaint, a Bench of the NHRC presided over by Member Priyank Kanoongo took cognisance of the matter under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, and directed the authorities to inquire into the allegations and submit reports within two weeks.

New Delhi, The National Human Rights Commission (NHRC) has sought action taken reports from the Central Board of Secondary Education (CBSE), the Jalna district administration and the Maharashtra Police over allegations that minor children were made to perform to an extremist Pakistani song during an annual day function at a school in Maharashtra's Jalna district.

Acting on a complaint, a Bench of the NHRC presided over by Member Priyank Kanoongo took cognisance of the matter under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, and directed the authorities to inquire into the allegations and submit reports within two weeks. As per a communication issued by the NHRC's Law Division on Wednesday, notices have been issued to the Chairman, CBSE, the District Magistrate, Jalna, and the Superintendent of Police, Jalna.

According to the complaint placed before the apex human rights body, the incident allegedly occurred during an annual day event at Kids World English School in Partur, Jalna district. The complainant alleged that "minor children were made to perform to an extremist Pakistani song promoting violence, accompanied by a background display of terrorist Mumtaz Qadri."

The complaint alleged that after he raised the issue in his capacity as a journalist, the school administration and the Jalna Police launched a retaliatory campaign against him.

"The complainant further alleged that following his journalistic whistleblowing to alert authorities, both the school administration and the Jalna police have launched a retaliatory campaign, issuing formal takedown notices to X and threatening him with criminal cases to suppress the investigation," the NHRC said.

Seeking intervention by the apex human rights body, the complainant requested a formal cognisance of the alleged extremist content displayed during the school function, an independent inquiry into the alleged administrative intimidation, and protection for investigative journalists from retaliatory law enforcement action.

Taking note of the allegations, the NHRC observed that the "prima facie seem to be violations of the human rights of the victims". It directed the CBSE Chairman, the District Magistrate and the Superintendent of Police, Jalna, "to get the allegations made in the complaint inquired into and to submit an Action Taken Report within two weeks for perusal of the Commission."



Source: <https://www.thehansindia.com/news/national/nhrc-seeks-reports-from-cbse-maharashtra-officials-over-allegation-of-extremist-content-at-school-event-1090128>

NHRC seeks reports from CBSE, Maharashtra officials over allegation of extremist content at school event
New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought action taken reports from the Central Board of Secondary Education (CBSE), the Jalna district administration and the Maharashtra Police over allegations that minor children were made to perform to an extremist Pakistani song during an annual day function at a school in Maharashtra's Jalna district. Acting on a complaint, a Bench of the NHRC presided over by Member Priyank Kanoongo took cognisance of the matter under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, and directed the authorities to inquire into the allegations and submit reports within two weeks. As per a communication issued by the NHRC's Law Division on Wednesday, notices have been issued to the Chairman, CBSE, the District Magistrate, Jalna, and the Superintendent of Police, Jalna.

According to the complaint placed before the apex human rights body, the incident allegedly occurred during an annual day event at Kids World English School in Partur, Jalna district. The complainant alleged that "minor children were made to perform to an extremist Pakistani song promoting violence, accompanied by a background display of terrorist Mumtaz Qadri." The complainant alleged that after he raised the issue in his capacity as a journalist, the school administration and the Jalna Police launched a retaliatory campaign against him. "The complainant further alleged that following his journalistic whistleblowing to alert authorities, both the school administration and the Jalna police have launched a retaliatory campaign, issuing formal takedown notices to X and threatening him with criminal cases to suppress the investigation," the NHRC said. Seeking intervention by the apex human rights body, the complainant requested a formal cognisance of the alleged extremist content displayed during the school function, an independent inquiry into the alleged administrative intimidation, and protection for investigative journalists from retaliatory law enforcement action. Taking note of the allegations, the NHRC observed that the "prima facie seem to be violations of the human rights of the victims". It directed the CBSE Chairman, the District Magistrate and the Superintendent of Police, Jalna, "to get the allegations made in the complaint inquired into and to submit an Action Taken Report within two weeks for perusal of the Commission."

Source: <https://www.edexlive.com/amp/story/news/nhrc-seeks-reports-from-cbse-maharashtra-officials-over-allegation-of-extremist-content-at-school-event>

NHRC seeks reports from CBSE, Maharashtra officials over allegation of extremist content at school event
According to the complaint placed before the apex human rights body, the incident allegedly occurred during an annual day event at Kids World English School in Partur, Jalna district.

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought action taken reports from the Central Board of Secondary Education (CBSE), the Jalna district administration and the Maharashtra Police over allegations that minor children were made to perform to an extremist Pakistani song during an annual day function at a school in Maharashtra's Jalna district.

Acting on a complaint, a Bench of the NHRC presided over by Member Priyank Kanoongo took cognisance of the matter under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, and directed the authorities to inquire into the allegations and submit reports within two weeks. As per a communication issued by the NHRC's Law Division on Wednesday, notices have been issued to the Chairman, CBSE, the District Magistrate, Jalna, and the Superintendent of Police, Jalna.

According to the complaint placed before the apex human rights body, the incident allegedly occurred during an annual day event at Kids World English School in Partur, Jalna district. The complainant alleged that "minor children were made to perform to an extremist Pakistani song promoting violence, accompanied by a background display of terrorist Mumtaz Qadri."

The complaint alleged that after he raised the issue in his capacity as a journalist, the school administration and the Jalna Police launched a retaliatory campaign against him.

"The complainant further alleged that following his journalistic whistleblowing to alert authorities, both the school administration and the Jalna police have launched a retaliatory campaign, issuing formal takedown notices to X and threatening him with criminal cases to suppress the investigation," the NHRC said.

Seeking intervention by the apex human rights body, the complainant requested a formal cognisance of the alleged extremist content displayed during the school function, an independent inquiry into the alleged administrative intimidation, and protection for investigative journalists from retaliatory law enforcement action.

Taking note of the allegations, the NHRC observed that the "prima facie seem to be violations of the human rights of the victims". It directed the CBSE Chairman, the District Magistrate and the Superintendent of Police, Jalna, "to get the allegations made in the complaint inquired into and to submit an Action Taken Report within two weeks for perusal of the Commission."



Source:

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/thiruvananthapuram/chief-minister-v-d-satheesan-seeks-joint-action-with-neighbouring-states-against-drug-trafficking/articleshowprint/131971217.cms?val=3728>

Chief minister V D Satheesan seeks joint action with neighbouring states against drug trafficking

Thiruvananthapuram: Seeking support to intensify efforts against interstate drug trafficking, chief minister V D Satheesan wrote to his Karnataka, Tamil Nadu and Puducherry counterparts, proposing closer coordination and joint action under the state's anti-drug campaign, Operation Toofan. In his letter, the chief minister said Kerala has strengthened intelligence-led enforcement measures as part of Operation Toofan, targeting drug trafficking networks, dismantling their financial channels and confiscating illegally acquired assets. He noted that drug trafficking syndicates operate across multiple states, making coordinated action among neighbouring states and Union territories essential. Border areas between Kerala and Karnataka, Tamil Nadu and Puducherry, as well as major road corridors, tourist destinations, student networks and urban distribution centres, are vulnerable to exploitation by narcotics mafias, he said. Satheesan pointed out that Kerala Police arrested several interstate and international drug traffickers and stressed that real-time intelligence sharing, joint operations and coordinated planning are crucial to effectively combat such networks. The chief minister proposed convening a high-level meeting of officials from all these four states to formulate a common action plan against interstate drug smuggling. He also informed the neighbouring states that home minister Ramesh Chennithala, state police chief Ravada Chandrasekhar and task commander Putta Vikramaditya are prepared to hold discussions with police chiefs and senior home department officials from the other states to strengthen collaborative efforts against narcotics trafficking.

Source: <https://www.thehindu.com/news/national/kerala/thrikkakara-municipality-installing-fencing-along-road-after-fatal-fall-of-girl-triggers-protests/article71142357.ece/amp/>

Thrikkakara municipality installing fencing along road after fatal fall of girl triggers protests

Three days after a 12-year-old girl died after falling nearly 20 feet from an elevated municipal road while riding her bicycle at Mavelipuram in Kakkanad, the Thrikkakara municipality has begun constructing a protective fencing along the accident stretch, amid mounting criticism over alleged negligence in providing safety measures. The municipality decided to erect the fencing using its own funds after the death of Rihana Kathrine Andrews, a Class VII student, on Sunday (June 21, 2026) sparked widespread outrage and safety concerns. She was riding her bicycle near her residence when she lost control and fell into the premises of an apartment complex below after the cycle hit the edge of the elevated road.

The girl succumbed to severe head injuries. Local people in the area, including residents of the flat complex, had alleged that the municipality had raised the road level and laid interlocking tiles without installing adequate protective barriers despite the sharp drop along the stretch. Municipal chairperson Rashid Ullampilly said the local body had issued a show-cause notice to the official responsible for the delay in acting on the representation seeking a protection wall at the accident site. "Along with putting up a fencing at the site, we have initiated measures to prevent similar incidents elsewhere. An official has been assigned to identify other hazardous locations within the municipality, and fencing or protective barriers will be installed wherever required," he said. The opposition Left Democratic Front's councillors and activists of the Democratic Youth Federation (DYFI) had staged a sit-in in front of the PWD wing of the municipality on Tuesday (June 23, 2026), accusing the civic body of criminal negligence. On Wednesday (June 24, 2026), Students Federation of India activists also took out a protest march to the municipal office. The Child Welfare Committee (CWC) has filed a complaint with the Thrikkakara police seeking to register a case against the municipality. "We have registered a case over unnatural death, and further actions will be taken based on all aspects including reports from the departments concerned," a police officer said. Meanwhile, the State Human Rights Commission (SHRC) on Wednesday ordered a high-level probe into the incident. SHRC Chairperson Alexander Thomas ordered the District Collector to assign an officer of the rank of Revenue Divisional Officer or Sub-Collector to inspect the site. An Assistant Commissioner of Police and a PWD engineer selected by the Collector also should take part in the inspection. The Collector, Principal Secretary to the Local Self-Government department, and Thrikkakara municipal secretaries have been asked to submit separate reports to the Commission on the incident within four weeks.

DATE	CHANNEL	TIME	DETAILS	DURATION	PROGRAM	AUTHOR	PERSONALITY
24.06.2026	Bharat Samachar	15:00	उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक दोना फैक्ट्री में मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का एक रोंगट खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दो साल से बंधक बनाकर रखे गए १२ मजदूरों को पुलिस ने छापेमारी कर मुक्त कराया है। इस अमानवीय घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला और इसे 'टूटी हुई कानून व्यवस्था' का सीधा नतीजा बताया।	10:51 Min	Samachar	Aditya	
24.06.2026	DD NEWS CHHATTISGARH	18:00	कबीरधाम में मानव तस्करी और बाल श्रम का भंडाफोड़, 13 बैगा आदिवासी बच्चे मुक्त	01:39 Min	Breaking News	Abc	

24.06.2026	Kanak News	16:00	<p>NH-16 Labour Trafficking Scam Exposed, Youth Cheated</p> <p>-A shocking labour trafficking and job fraud network has been exposed near National Highway-16 in Odisha.</p> <p>Hundreds of young job seekers are allegedly being lured with promises of foreign employment, only to fall into a trap run by middlemen and fake recruitment agents.</p> <p>According to reports, a so-called “job qualification office” has been operating along National Highway 16 where youths are being encouraged to pay large sums of money for overseas jobs.</p> <p>After reaching foreign countries, many workers are reportedly facing exploitation, poor living conditions, and harassment. When complaints are raised, the recruiting agencies allegedly refuse responsibility.</p>	03:41 Min	Breaking News	Sarita	
------------	------------	-------	---	-----------	---------------	--------	--

24.06.2026	Argus News	16:15	<p>Mob Lynching in Odisha: 8 Years of Injustice from Rayagada to Baliana</p> <p>- Odisha Crime Branch, Tuesday apprehended another key accused in the sensational murder of 32-year-old GRP constable Soumya Ranjan Swain under Baliana police limits in Bhubaneswar, officials said.</p> <p>With the latest apprehension, the total number of accused arrested in connection with the case has risen to 19. The accused, identified as Bibhuti Bhusan Parida alias Happy (26), a resident of Benupur under Baliana, was nabbed during a late-night operation in the Bidanashi area of Cuttack.</p>	04:20 Min	Breaking News	Abc	
------------	------------	-------	---	-----------	---------------	-----	--

